



2026:AHC:35303

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए क्रमांक 1192/2026

राम ब्रजेश

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : दुर्गा तिवारी

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री दुर्गा तिवारी और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गया प्रसाद की दलीलें सुनी गई।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गया प्रसाद द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उनका कहना है कि वे निर्देशों से भलीभांति परिचित हैं और ये निर्देश रिट याचिका के निपटारे के लिए पर्याप्त हैं। वे कोई और हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 02.01.1996 को तहसील बह, जिला आगरा में मौसमी संग्रह चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था, हालांकि, 13.10.2025 को, बिना किसी सूचना या अवसर के, उप-विभागीय अधिकारी, आगरा द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश पारित किया गया।
4. इसी बात पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. दिनांक 30.01.2026 के आदेश पारित होने के बाद, आज आगरा के उप-विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांक 13.02.2026 को निर्देश अग्रेषित किए गए हैं, जिन्हें अभिलेख में ले लिया गया है और परिशिष्ट ए के रूप में चिह्नित किया गया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि चुनौती दिए गए आदेश को इस साधारण कारण से भी मान्य नहीं ठहराया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के अनुसार, वह 2.01.1996 से मौसमी संग्रह चपरासी के रूप में कार्यरत है, लेकिन याचिकाकर्ता की सेवा को समाप्त नहीं किया जा सकता था। यह कार्रवाई मात्र इस आरोप पर की गई है कि प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र संदिग्ध हैं। निवेदन यह है कि यदि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई पूर्व सूचना थी, तो याचिकाकर्ता को इस संबंध में सूचित किया जाना चाहिए था और उसकी बात सुनी जानी चाहिए थी।

7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गया प्रसाद ने प्रस्तुत किया कि निर्देशों के अनुसार, पैरा-6 में इस तथ्य का उल्लेख है कि याचिकाकर्ता की मौसमी संग्रह चपरासी के रूप में नियुक्ति 03.09.1991 को हुई थी और नियुक्ति की तिथि पर वह नाबालिग था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि नियुक्ति की तिथि पर याचिकाकर्ता उपयुक्त नहीं था, इसलिए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

9. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को मौसमी संग्रह चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि याचिकाकर्ता ने याचिका के अनुलग्नक-3 में कहा है कि उसे 02.01.1996 को नियुक्त किया गया था, लेकिन प्रतिवादियों के अनुसार, निर्देशों के मुताबिक उसे 03.08.1991 को नियुक्त किया गया था। चुनौती दिए गए आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता संदिग्ध थे और इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं थी, हालांकि, निर्देशों के अनुसार, कमी यह पाई गई कि याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति की तारीख पर नाबालिग था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से यह पूछे जाने पर कि क्या याचिकाकर्ता लंबे समय से सेवा कर रहा है, इस तथ्य को देखते हुए याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था, उत्तर नकारात्मक है।

11. हालांकि, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता की सुनवाई की जाए और आदेश पारित किए जाएं।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस प्रकार की दलील पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

13. विरोधी पक्षों की दलीलों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता दूसरे प्रतिवादी, जिला मजिस्ट्रेट, आगरा के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट, आगरा, 13.03.2026 तक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय कानून के अनुसार उचित समय सीमा के भीतर करेगा। आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि।

14. यदि विवादित आदेश पारित करते समय कोई अग्रिम सूचना दी गई हो, तो याचिकाकर्ता को वह सूचना उपलब्ध कराई जाएगी और उसे उस सूचना को वापस लेने का अवसर दिया जाएगा।

15. दिनांक 13.10.2025 का आदेश पारित होने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगा।

16. तदनुसार, रिट याचिका का **खारिज** कर दिया गया है।

फरवरी 17, 2026

आशू

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”